आरएनआर

न्यायमूर्ति के. कन्नन के समक्ष

राजेश कुमार (आर. के. भनोट) - याचिकाकर्ता

बनाम

रमिंदर जैन व अन्य, - प्रतिवादी

ई.ए.ओ. 1990 का क्रमांक 935

17 जनवरी. 2011

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226—टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा 17 मार्च 1978 को जारी सर्कुलर नंबर 1—साइकिल सवार से टकराने से बचाव करते हुए एक निजी कार की दुर्घटना—चालक ने वाहन को एक तरफ चलाया और पेड़ से जा टकराया—ट्रिब्यूनल ने चालक की लापरवाही का कोई सबूत नहीं पाया और बर्खास्त कर दिया दावा याचिका—उसे चुनौती—ट्रिब्यूनल पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज न करने के तथ्य या चालक के साक्ष्य को यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं मान सकता था कि चालक की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी—कार के चालक को लापरवाही का दोषी ठहराया गया—दुर्घटना के लिए जिम्मेदार— बीमा कंपनी की देनदारी का मुद्दा - बीमा पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है - दुर्घटना के लिए बीमा कंपनी को

जिम्मेदार ठहराया जाता है - अपील की अनुमति है।

अभिनिर्धारित किया गया कि दावों से उत्पन्न दावे के लिए उत्तरदाताओं के बीच जिम्मेदारी के मुद्दे का पता लगाए बिना मामला समाप्त नहीं हो सकता। यदि जिस कार में दावेदार यात्रा कर रहे थे उसका चालक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था, तो बीमा कंपनी की देनदारी का मुद्दा बीमा पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर होगा। यह पॉलिसी निजी कार के लिए एक व्यापक पॉलिसी के रूप में जारी की गई है और रुपये 2826 के प्रीमियम एकत्र किए गए थे, 'पॉलिसी की शुरुआत 24 फरवरी 1989 को हुई थी और यह दुर्घटना पॉलिसी की लागू रहने के दौरान, अर्थात् 7 मार्च 1989 को हुई थी।धारा II(I)(a) के माध्यम से मोटर वाहन में ले जाए जाने वाले यात्री के जोखिम को कवर करने के लिए विशिष्ट निगमन किया गया है। बीमा कंपनी, इसलिए, दुर्घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और बीमाकर्ता का तर्क कि प्रीमियम का भुगतान केवल वाहन को हुए नुकसान के लिए किया गया था, पॉलिसी की गलत रीडिंग है। नीति में वही शामिल है जो 17 मार्च 1978 को जारी परिपत्र संख्या 1 में स्पष्ट रूप से सभी बीमा कंपनियों के लिए टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा कहा गया था।

(पैरा 5 एवं 6)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश शर्मा ।

-अधिवक्ता प्रीतम सैनी और रजनीश नरूला, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या / की ओर से ।

अधिवक्ता पॉल एस सैनी. और अनिल कुमार. बीमा कंपनी की ओर से।

न्यायमूर्ति के. कन्नन, (मौखिक)

(1) दोनों अपीलें जुड़ी हुई हैं क्योंकि वे एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हुई हैं और उस मामले में मुआवजे की मांग की गई है जहां याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। दावेदार एक निजी कार में सवार थे और वाहन के मालिक का भाई उसे चला रहा था। एक साइकिल सवार से टकराने से बचने के प्रयास में, चालक ने वाहन को एक तरफ मोड़ दिया और अंततः एक नीम के पेड़ से जा टकराया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और ड्राइवर ने खुद इस बात का सबूत दिया था कि वह 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन सावधानी से चला रहा था और एक साइकिल चालक से टकराने से बचने के प्रयास के कारण ही दुर्घटना हुई थी। ट्रिब्यूनल ने माना कि ड्राइवर की लापरवाही का कोई सबूत नहीं है और याचिका खारिज कर दी।

(2) किसी साइकिल चालक से टकराने से रोकने के लिए ड्राइवर के प्रयास का परिणाम यह होना चाहिए कि स्टीयरिंग सुरक्षित रूप से साफ रहे और फिर भी उसी सड़क पर चलती रहे। यदि ड्राइवर को अंततः यह पता चलता है कि वाहन को केवल पेड़ से टकराकर ही रोका जा सकता

है, तो ड्राइवर की लापरवाही एक स्पष्ट निष्कर्ष है जिस पर कोई भी पहुँच सकता है। ट्रिब्यूनल पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज न करने के तथ्य या ड्राइवर के साक्ष्य को यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं मान सकता था कि ड्राइवर की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। आख़िरकार। एक पेड़ है. चीजों की प्रकृति से, स्थिर और वाहन चलाने वाले व्यक्ति के लिए पेड़ के संपर्क में आए बिना रुकने के लिए स्पष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए। फिर कोई पेड़ सड़क के बीच में नहीं हो सकता. यह सड़क के अंतिम छोर से परे होना चाहिए और किसी भी वाहन के पेड़ से टकराने पर, इसके परिणामस्वरूप रिप्स लोकीफ़र स्थिति का अनुमान लगाया जाना चाहिए जो चालक की लापरवाही और लापरवाही से ड्राइविंग को इंगित करता है। इसलिए, मैं लापरवाही के संबंध में निष्कर्ष को खारिज कर देता हूं और उस वाहन के चालक को लापरवाही का दोषी मानता हूं जिसमें यात्री यात्रा कर रहे थे।

(3) दावेदार अर्थात् डॉ. टी.पी. के लिए मुआवजे का दावा। मामले को खारिज करने के बावजूद ट्रिब्यूनल द्वारा भनोट का मूल्यांकन किया गया था और ट्रिब्यूनल ने पाया कि वह एक डॉ. एमएल कोचर (पीडब्ल्यू 7) के इलाज के अधीन थे और उन्होंने खुद दावेदार को 10% स्थायी विकलांगता और 5% अस्थायी विकलांगता का सामना करने के लिए प्रमाणित किया था। उसे लगी चोटों के कारण. डॉ. एसके मोडा (पीडब्लू3) ने भी डॉ. जेपी भनोट को लगी चोटों और उनके द्वारा दिए गए उपचार के लिए गवाही दी थी। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने विवरणों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि याचिका धारा 110-ए के तहत दायर की गई थी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का पता लगाए बिना मुआवजा संभव नहीं हो सकता था। ट्रिब्यूनल ने राजेश कुमार भनोट के मुआवजे के आकलन पर भी निर्णय नहीं लिया था जो कि 1990 के ईएओ नंबर 935 में अपील का विषय है। चूंकि अपील वर्ष 1990 से संबंधित है और दुर्घटना वर्ष 1989 में हुई थी।1 जांच के लिए आगे बढ़ें क्वांटम के मुद्दे को अनावश्यक रूप से ट्रिब्यूनल के माध्यम से केवल इस पहलू पर विचार करने के लिए डाले बिना। जहां तक डॉ. जेपी भनोट के दावे का सवाल है। मेडिकल सर्टिफिकेट से पता चला कि उन्हें 7 मार्च 1989 से 21 मार्च 1989 और फिर 21 मार्च 1989 से 2 मई 1989 तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कहा जाता है कि वह हरियाणा के कीट विज्ञान विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे
और वह रुपये 4.075 , 3.700-5,700 के पैमाने में वेतन ले रहा था। PW7 ने कहा था कि चोटों के कारण, दावेदार का अंग 1 सेमी छोटा हो गया था और इस तरह के छोटे होने के कारण, 4% स्थायी विकलांगता थी और 6% स्थायी विकलांगता पार्श्व एन्यूलेशन के साथ छोड़े गए मैल-यूनाइटेड फ्रैक्चर शाफ्ट फीमर के कारण थी। प्रमाणीकरण को ध्यान में रखते हुए, उन्हें 2 जुलाई 2009 तक आराम करने की सलाह दी गई थी। मैं यह मानूंगा कि वह 4 महीने की अवधि के लिए

ड्यूटी करने में असमर्थ थे और आय का नुकसान रु 16,000 (रु. 4,000 x 4 = 16,000) था। उनके फ्रैक्चर और लंबे समय तक चले इलाज के लिए मैं दर्द और पीड़ा के लिए रुपये 15,000 प्रदान करूंगा। सबूत यह था कि उनकी श्रोणि की हड्डी टूट गई थी और बायां कंधा और पसलियां पूरे शरीर में खिसक गई थीं। प्लास्टर के माध्यम से फ्रैक्चर को कम किया गया और 50/60 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के लिए उन्होंने रुपये खर्च किए थे। चिकित्सा व्यय के लिए 10,000 और रु. 5,000 परिवहन व्यय के लिए मैं उसे वही अनुदान देता हूं। उस असुविधा और सुविधाओं के नुकसान के लिए जो उसे एक अंग छोटा होने के कारण गंभीर विकलांगता के कारण झेलनी पड़ती, मैं रुपये 10,000 उपलब्ध कराऊंगा। कुल मुआवजा रु. 56,000 होगा और यह बीमा कंपनी द्वारा याचिका की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% ब्याज के साथ देय होगा।

(4) जहां तक राजेश कुमार भनोट के मुआवजे के दावे का संबंध है, सबूत यह था कि उनके दाहिने घुटने पर 2x2 सेमी की हड्डी में गहरी चोट थी और छाती क्षेत्र के नीचे उनकी पसलियां बुरी तरह से दब गई थीं और उनकी नाक से खून बह रहा था। उन्होंने इस आशय का साक्ष्य दिया कि उन्हें रोहतक के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्होंने शिकायत की कि दौड़ने की स्थिति में उनके दाहिने पैर में अभी भी दर्द रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने रुपये 2,000 खर्च किये हैं और चूँकि उनके भाई डॉ. जे.पी.भनोट अस्पताल में भर्ती एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आते थे इसलिए, आय का नुकसान हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें रुपये 2,000 से रु. 5,000 की मासिक आय का नुकसान हुआ है। किसी भी तरह से आय की हानि स्थापित नहीं हुई और मैं उसे रुपये 5,000 का मुआवजा दर्द और पीड़ा और अस्पताल में भर्ती होने की छोटी अवधि के लिए प्रदान करूंगा, जिस पर याचिका की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% की दर से ब्याज लगेगा। इसी प्रकार, दुर्घटना कारित करने में लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के लिए भुगतान करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व कार के चालक का होगा।

(5) दावों से उत्पन्न दावे के लिए उत्तरदाताओं के बीच जिम्मेदारी के मुद्दे का पता लगाए बिना मामला समाप्त नहीं हो सकता है। यदि जिस कार में दावेदार यात्रा कर रहे थे उसका चालक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था, तो बीमा कंपनी की देनदारी का मुद्दा बीमा पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर होगा। मैंने न्यायालय में दायर और पीडब्लू8/बी के रूप में प्रदर्शित बीमा पॉलिसी देखी है, यह पॉलिसी निजी कार के लिए एक व्यापक पॉलिसी के रूप में जारी की गई है और रुपये 2,826 के प्रीमियम एकत्र किया गया। पॉलिसी की शुरुआत 24 फरवरी 1989 को हुई थी और यह दुर्घटना पॉलिसी की मुद्रा के दौरान, अर्थात् 7 मार्च1989 को हुई थी।मैं इस मामले में पता हूँ की, धारा II (एल) (ए) के माध्यम से एक मोटर वाहन में ले जाए जाने वाले व्यक्ति के जोखिम को निम्नलिखित

शब्दों में कवर करने के लिए विशिष्ट निगमन किया गया है:

> ले जाए गए लोगों सहित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट, बशर्ते कि ऐसे लोगों को किराए या इनाम के लिए नहीं ले जाया जाए, लेकिन तब तक जब तक धारा 92/आई और धारा 95 मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। जहां बीमाधारक द्वारा ऐसे व्यक्ति के रोजगार के दौरान ऐसी मृत्यु या चोट उत्पन्न होती है तो कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। "

(6) इस लिये बीमा कंपनी दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और बीमाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलील कि प्रीमियम का भुगतान केवल वाहन को हुए नुकसान के लिए किया गया था, पॉलिसी की गलत व्याख्या है। नीति में वही शामिल है जो 17 मार्च 1978 को जारी परिपत्र संख्या 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया था। सभी बीमा कंपनियों के लिए टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा।

(7) इसलिए, बीमा कंपनी इन दो याचिकाओं से उत्पन्न होने वाले दावों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होगी।

(8) उपरोक्त सीमा तक दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा

आरएनआर